दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, सोमवार 16 दिसम्बर 2019 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 78

महत्वपूर्ण एवं खास

जैसलमेर में सेना के ट्रक और टर्बो में भीषण टक्कर, 13 जवान घायल

जैसलमेर (आरएनएस)। सर्दी व कोहरे की मार आज जैसलमेर में भी देखने को मिली। इसी बीच आज अल सुबह घने कोहरे के चलते सोनू गांव के पास सेना के ट्रक और एक सिविल टर्बो की आपस में भिड़ंत हो गई। भिडंत इतनी भीषण थी कि दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए। भिड़ंत में 13 जवान घायल हो गए हैं। घायल जवानों में से कईयों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, सेना के ट्रक में कुल 21 जवान सवार थे जिसमें से 13 जवानों को गंभीर चोटें आई हैं। 3 से 4 जवानों को हेड इंजरी हुई है जिन्हें इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया गया है। इस एक्सिडेंट में टर्बो चालक की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ये हादसा सोनू माइंस गांव के करीब हुआ। ट्रक सोनू माइंस से आ रहा था जबकि ट्रक जैसलमेर से रामगढ़ की ओर जवानों को लेकर जा रहा था।

बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह को बम से उड़ाने की कोशिश

» कार पर ईंटों से भी किया हमला

कोलकाता (आरएनएस)। पश्चिम बंगाल में फिर भाजपा नेता पर हमला हुआ है। इस बार हमला बैरकपुर से भाजपा के सासंद अर्जुन सिंह पर हमला हुआ है। सांसद अर्जुन सिंह ने कहा है कि उन्हें बम से उड़ाने की कोशिश की गई है। मीडिया से बातचीत करते हुए अर्जुन सिंह ने कहा कि ' कांकिनारा से लौटते वक्त मेरी कार पर कुछ असामाजिक तत्वों ने ईट से हमला किया और फिर कार पर एक बम फेंका गया। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए।' इस हमले में भाजपा सांसद अर्जुन सिंह की कार का शीशा टूट गया। हालांकि सांसद इस हमले में बाल-बाल बच गए। भाजपा सांसद ने इस हमले का सीधा आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया है। सांसद की कार पर तब हमला किया गया जब वो कंकिनारा से लौट रहे थे। सूत्रों के अनुसार, अर्जुन सिंह की कार के पर पहले तो ईट पत्थर से हमला किया फिर उसके पास एक बम भी फेंक दिया गया। हमले के बाद अर्जुन सिंह ने कहा टीएमसी ने गुंडों ने मेरी कार पर ईट फेंके।

अर्थव्यवस्था सुधार के लिए सुझावों पर गौर करेगी सरकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण वित्तवर्ष 2020-21 के बजट में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने खातिर सेक्टोरियल इंटरवेंशन के लिए तैयार हैं, अगर सुझाव बजट पूर्व परामर्श के दौरान उनके नोटिस में लाए जाते हैं। यह बजट पूर्व परामर्श सोमवार से शुरू हो रहे हैं। अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए नीति और वित्तीय प्रोत्साहन की श्रृंखला के बाद मंत्री अब केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो सिर्फ45 दिन बाद है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि नीतिगत हस्तक्षेप जल्द ही परिणाम देने शुरू कर देंगे। विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में हमने मांगों के अनुसार दखल दिया है। मैं इन कदमों के परिणामों को देखने को उत्सुक हूं। हम सोमवार से बजट-पूर्व परामर्श शुरू कर रहे हैं।

किसानों की आय दोगुना करने पर संसदीय समिति ने की सिफारिश

» कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा आवंटन में वृद्धि जरूरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग ने कहा है कि कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के लिये आवंटन को बढ़ाकर कृषि सकल घरेलू उत्पाद का 1 प्रतिशत किया जाए, ताकि 2022 तक किसानों की आय दोगुणा करने तथा भारत को 5000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

संसद में हाल ही में पेश कृषि संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर खर्च दक्षिण अफ्रीका और चीन जैसे देशों से कम है तथा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग को आवंटित बजट का 75 प्रतिशत वेतन, पेंशन आदि पर खर्च हो जाता है । इस प्रकार अनुसंधान कार्यकलापों पर केवल 25 प्रतिशत राशि ही शेष बचती है। वहीं विभाग के प्रतिनिधियों ने कृषि संबंधी संसद की स्थायी समिति को यह बात बतायी। समिति ने विभाग से इस विषय को वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले पांच वर्षो के दौरान कृषि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा का अंश 0.61 प्रतिशत रहा है जो अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। चीन कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा पर अपने कृषि सकल घरेलू उत्पाद का एक प्रतिशत खर्च करता है। दक्षिण अफ्रीका सहित कई छोटे देश भी कृषि अनुसंधान पर भारत से अधिक खर्च करते हैं। समिति को यह बताया गया कि विभाग इस बात पर जोर दे रहा है कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिये आवंटन को बढ़ाकर कृषि सकल घरेलू उत्पाद का 1 प्रतिशत कर दिया जाए। रिपोर्ट के अनुसार समिति को यह भी बताया गया कि 2022 तक किसानों की आय दोगुणा करने तथा भारत को 5000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिये कृषि अनुसंधान में अधिक निवेश आवश्यक है तथा इसके बिना इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। समिति का मत है कि चूंकि आवंटित निधियों का बड़ा भाग वेतन, पेंशन आदि पर खर्च हो जाता है इसलिये कृषि अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये विभाग को और निधियां प्रदान की जानी चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है, कि कृषि क्षेत्र के महत्व और सकल घरेलू उत्पाद में इसके योगदान को देखते हुए समिति सिफारिश करती है कि विभाग इस मामले को वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाये ताकि कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिये आवंटन के प्रतिशत अंश में धीरे धीरे बढ़ोत्तरी की जा सके।

केंद्रीय मंत्रियों के कामकाज का आकलन करेंगे पीएम मोदी

» मंत्रालय के रिपोर्ट कार्ड के साथ तलब किये गये मंत्री

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिसंबर को सभी मंत्रियों को रिपोर्ट कार्ड लेकर सात लोक कल्याण रोड स्थित अपने आवास पर तलब किया है। इस दिन उनके सामने सभी मंत्री प्रजेंटेशन देंगे।

सूत्रों के मुताबिक, लचर प्रदर्शन वाले मंत्रियों पर आगे हटाने की कार्रवाई की जा सकती है। इस अहम मीटिंग के मद्देनजर मोदी कैबिनेट के बहुप्रतीक्षित विस्तार की अटकलें जोर पकड़ रही हैं। सूत्रों ने कहा कि इस मीटिंग में गृह मंत्री और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग के जरिए पीएम पता करना चाहते हैं कि उनकी प्राथमिकता वाली योजनाओं का किस मंत्रालय में क्या हाल है? कमजोर प्रदर्शन करने वाले मंत्रालयों के मंत्री हटाए जा सकते हैं। इसके अलावा एक साथ कई बड़े मंत्रालय चला रहे मंत्रियों से कुछ विभाग लेकर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। बता दें कि 30 मई 2019 को शपथ लेने के छह महीने बाद भी मोदी कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है, जबकि 2014 में मई में सरकार बनने के छह महीने में ही 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पहला कैबिनेट विस्तार किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 30 मई को 57 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। नियमों के मुताबिक लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत यानी अधिकतम 81 मंत्री बनाए जा सकते हैं। पिछली सरकार में मोदी सरकार में 70 मंत्री थे।

शूटर वर्तिका खुद देना चाहती हैं दोषियों को फांसी, शाह को खून से लिखा पत्र

» निर्भया केस

नईदिल्ली (आरएनएस)। अंतर्राष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खून से एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने निर्भया के दोषियों को महिला द्वारा फांसी दिए जाने की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह ने पत्र में लिखा है कि निर्भया मामले के दोषियों को फांसी मेरे द्वारा दी जानी चाहिए। इससे पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि एक महिला भी फांसी की सजा दे सकती हैं। मैं चाहती हूं कि महिला कलाकार, सांसद मेरा समर्थन करें। मुझे उम्मीद है कि ये समाज में बदलाव आएगा।

बता दें कि तिहाड़ जेल में बंद निर्भया बलात्कार-हत्याकांड के चारों दोषी अवसाद में हैं और उन्होंने खाना-पीना भी कम कर दिया है। जेल के सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि चारों दोषियों- अक्षय, मुकेश, पवन गुप्ता और विनय शर्मा के साथ चार-पांच सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है, ताकि वे खुद को कोई नुकसान न पहुंचा सकें। गौरतलब है कि 16 दिसंबर, 2012 की शाम दक्षिणी दिल्ली के मुनीरका बस स्टॉप पर एक खाली प्राइवेट बस में अपने दोस्त के साथ चढ़ी 23 वर्षीय पैरा मेडिकल छात्रा के साथ छह लोगों ने चलती बस में गैंगरेप किया और क्रूरता की सारी हदें पार करने के बाद उसे और उसके दोस्त को महिपालपुर में सड़क किनारे फेंक दिया था।

अनशन पर बैठी स्वाति मालीवाल की तबीयत बिगड़ी

» बेहोश होने के बाद एलएनजेपी हॉस्पिटल में कराया भर्ती

नईदिल्ली (आरएनएस)। देशभर में बढ़ते बलात्कार के विरोध में और बलात्कारियों को फांसी की मांग को लेकर अनशन पर बैठी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल की हालत बिगड़ गई है। उन्हें एलएनजेपी हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। बता दें कि महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल पिछले 13 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं। शनिवार को डॉक्टर्स ने उन्हें अनशन खत्म करने को कहा था। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर स्वाति मालीवाल अनशन खत्म नहीं कि तो उनके शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उनकी किडनी खराब हो सकती है।

बता दें कि भूख हड़ताल के चलते स्वाति मालीवाल का वजन घट गया है। स्वाति मालीवाल इतनी कमजोर हो गई हैं, कि वह बात भी नहीं कर पा रही हैं। रविवार की सुबह वह बेहोश हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया।

इससे पहले देशभर में दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं के विरोध में राजघाट पर आमरण अनशन पर बैठीं स्वाति मालीवाल ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। मालीवाल ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि दिशा कानून को तत्काल प्रभाव से पूरे देश में लागू किया जाए।

आंध्र प्रदेश सरकार ने यौन अपराधों व एसिड हमले के मामलों की सुनवाई के लिए राज्य में दिशा कानून लागू किया है। दिल्ली महिला अयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का कहना है कि उपवास पर बैठने से पहले भी उन्होंने पत्र लिखकर विशिष्ट मांगों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की थी लेकिन अफसोस कि प्रधानमंत्री ने इसका कोई जवाब नहीं दिया।

उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि आंध्र प्रदेश सरकार का इस दिशा में उठाया गया कदम उम्मीद जताता है। शुक्रवार को आंध्र प्रदेश विधानसभा में दिशा बिल पारित हुआ। मालीवाल ने कहा कि यह कानून महिलाओं के खिलाफ अपराधों में न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

देश में इस साल नौ शेरों का किया गया शिकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो में लगाई गई एक आरटीआई से कुछ महत्वपूर्ण खुलासे से पता चला है कि दिश में इस साल नौ शेरों का शिकार किया गया है।

समाजसेवी रंजन तोमर की आरटीआई के जवाब में यह तथ्य सामने आए हैं। तोमर लगातार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूचियों में विलुप्तप्राय होने की कगार पर खड़े जानवरों के लिए मांगी गई जानकारी में ब्यूरो ने बताया कि पिछले 11 सालों में करीब 439 शेरो को इस दौरान मार दिए जाने की जानकारी है। वहीं राष्ट्रीय हरित न्यायालय द्वारा कड़े रुख के कारण भी सरकारों ने यथोचित कदम उठाये हैं। शायद यह ही कारण है के पिछले दस सालों में जहाँ औसतन 430 शेरों का शिकार किया अर्थात 11 वर्षों में तकरीबन 439 शेर खो दिए गए, जिनमें इस साल शिकार में मारे गये 9 शेर भी शामिल हैं। इस साल यह आंकड़ा बेहद कम हुआ है, क्योंकि इससे पहले पिछले साल तक दस साल में 430 शेरो के शिकार होने से हर साल 43 शेरों के मारे जा रहे थे। आरटीआई के जवाब में ब्यूरो द्वारा जवाब दिया गया है के इस वर्ष (अक्टूबर तक) कुल 9 शेरो का शिकार हुआ है , हालाँकि यह कोई खुशी की बात नहीं है लेकिन पहले से कम शिकार होना जरूर एक अच्छी बात है। पर्यावरण प्रेमी जानते हैं के इस दुनिया में शेर की कितनी अहमियत है।

असम व मध्य प्रदेश में मारे गए ज्यादा शेर

आरटीआई के जवाब में कुछ बातें जो खुलकर सामने आई हैं उनमें पहली यह के आसाम राज्य में सबसे ज्यादा 4 शेरों का शिकार हुआ है मई से जुलाई के महीनों में घटित हुआ इस दौरान ब्यूरो एवं पुलिस द्वारा 12 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहाँ 3 शेरो को जनवरी से मार्च के बीच मार दिया गया, यहाँ भी 2 शेरों के शिकार में 8 शिकारियों को पकड़ा गया, जबकि एक शिकार में किसी को भी नहीं पकड़ा जा सका, इसके आलावा तेलंगाना में एक शेर का शिकार हुआ जबकि 6 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया एवं अंत में पश्चिम बंगाल में एक शेर को मारने के लिए 2 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया।

भारतीय मूल की टोनी सिंह बनीं मिस वर्ल्ड 2019

» सुमन राव तीसरे नंबर पर

लंदन। भारतीय मूल की जमैका की रहने वाली टोनी एन सिंह को मिस वर्ल्ड 2019 चुना गया। कार्यक्रम का आयोजन लंदन में किया गया था। 2018 की मिस वर्ल्ड वनेसा पोंस ने उनके सिर पर मिस वर्ल्ड का ताज सजाया। वनेसा मेक्सिको की रहने वाली हैं। 2019 में मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स दोनों अश्वेत सुंदरियां चुनी गई हैं। इससे पहले 8 दिसंबर को साउथ अफ्रीका की 26 साल की जोजिबिनी टुंजी मिस यूनिवर्स 2019 चुनी गई थीं।

इस साल ब्यूटी वर्ल्ड में भारत की सुमन राव ने भी देश का नाम रोशन किया है और वह मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में तीसरे नंबर पर रहीं। दूसरे नंबर पर मिस फ्रांस ओपेली मेजिनो रहीं। सुमन ने मिस वर्ल्ड एशिया 2019 का भी ताज अपने नाम किया है। इससे पहले जून में उन्हें मिस इंडिया 2019 चुना गया था।

20 साल की सुमन राव राजस्थान की रहने वाली हैं। वह अपना भविष्य बॉलीवुड में देख रही हैं। मिस इंडिया चुने जाने के बाद से वह लगातार मॉडलिंग असाइनमेंट में लगी हुई हैं। मिस वर्ल्ड टोनी सिंह की बात करें तो वह फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर चुकी हैं। वह साइकॉलजी की छात्रा हैं और डॉक्टर बनना चाहती हैं।

देश में बलात्कार के आरोपियों की दोषसिद्धि दर 32 प्रतिशत

नई दिल्ली (आरएनएस)। पूरे देश को हिलाकर रखने वाले निर्भया सामूहिक बलात्कार के सात साल बाद देश में बलात्कार के मामलों में दोषसिद्धि दर 32.2 प्रतिशत है। इस घटना के बाद यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए कानूनों को सख्त बनाये जाने के बावजूद बलात्कार के मामलों में दोषसिद्धि दर कम है।

वर्ष 2017 के लिए उपलब्ध राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार उस वर्ष बलात्कार के मामलों की कुल संख्या 1,46,201 थी, लेकिन उनमें से केवल 5,822 लोगों की दोषसिद्धि हुई। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 2017 में बलात्कार के मामलों में आरोप पत्र की दर घटकर 86.4 प्रतिशत रह गई जो 2013 में 95.4 प्रतिशत थी। अलवर बलात्कार मामले में बचाव पक्ष की वकील शिल्पी जैन ने कहा कि बलात्कार मामलों की जांच करने वाले पुलिस के क्षेत्र-स्तरीय कर्मचारियों को अधिक कुशल बनाने की आवश्यकता है। इस मामले में ओडिशा के पूर्व पुलिस महानिदेशक बी बी मोहंती के बेटे बिट्टी मोहंती ने एक विदेशी पर्यटक से बलात्कार किया था। जैन ने कहा कि वे ज्यादातर अनुभवहीन हैं और ताकत उनके सिर पर चढ़ जाती है और ज्यादातर मामलों में वे बेहद भ्रष्ट हैं। उन्होंने कहा कि एक उप-निरीक्षक उच्चतम स्तर का अधिकारी होता है जो आरोप पत्र दायर करता है, इसलिए कोई भी तथ्यों की गुणवत्ता की कल्पना कर सकता है। गौरतलब है कि दक्षिण दिल्ली में 23 वर्षीय एक छात्रा से वर्ष 2012 में 16 और 17 दिसम्बर की दरम्यानी रात में एक चलती बस में सामूहिक बलात्कार किया गया। सड़क पर फेंके जाने से पहले उस पर गंभीर रूप से हमला किया गया और 29 दिसम्बर को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी।

राहुल के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे सावरकर के पोते

» अजित पवार और देवेंद्र फ डणवीस ने भी की टिप्पणी

नई दिल्ली (आरएनएस)। विनायक दामोदर सावरकर पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी तूल पकड़ती जा रही है। इस मामले में सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने राहुल को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि वे सोमवार को उनके खिलाफ हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। वहीं इस मामले में महाराष्ट्र सरकार पर पडने वाले असर को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता अजित पवार ने कहा है कि उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी और शरद पवार परिपक्व लोग हैं और वे सही निर्णय ही लेंगे।

राहुल गांधी के सावरकर को लेकर दिये गये बयान पर रंजीत सावरकर ने महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार को सलाह दी है कि राहुल के इस बयान के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने मंत्रिमंडल से कांग्रेस के मंत्रियों को बर्खास्त करें और अल्पमत की सरकार चलाएं, क्योंकि भाजपा उनकी सरकार के खिलाफ वोट नहीं करेगी। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की सरकार है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फ्डणवीस ने भी शिवसेना पर हमला बोला है। फ्डणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र और देश सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। शिवसेना सत्ता में रहने के लिए कैसे-कैसे लोगों के साथ समझौते कर रही है ये साफ नजर आ रहा है। पहले शिवसेना सावरकर से जुड़े मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया देती थी और उनका बचाव करती थी, लेकिन अब वह नरम क्यों हो गई है।

कांग्रेस का दोहरा चरित्र उजागरः मायावती

बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर से कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला है। मायावती ने वीर सावरकर के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने रविवार को एक के बाद एक तीन ट्वीट किए। मायावती ने लिखा कि शिवसेना अपने मूल एजेंडे पर अभी भी कायम है, इसलिए इन्होंने नागरिकता संशोधन बिल पर केंद्र सरकार का साथ दिया और अब सावरकर को भी लेकर इनको कांग्रेस का रवैया बर्दाश्त नहीं है। किंतु फिर भी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना के साथ बनी हुई है तो यह सब कांग्रेस का दोहरा चरित्र नहीं है तो और क्या है? अतरू इनको, इस मामले में अपनी स्थिति जरूर स्पष्ट करनी चाहिए। वरना यह सब इनकी अपनी पार्टी की कमजोरियों पर से जनता का ध्यान बंटाने के लिए केवल कोरी नाटकबाजी ही मानी जाएगी। उल्लेखनीय है कि शनिवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में भारत बचाओ रैली के दौरान सावरकर को कठघरे में खड़ा कर दिया था।